तालों का निर्यात

4293. श्री सह्यानन्द जी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ में बने तालों की विदेशों में बहुत मांग है;

(ख) यदि हां, तो किन किन कम्पनियों ने तालो के निर्यात का निर्णय किया है;

(ग) क्या सरकार ने इन कम्पनियों को कुछ सहायता देने का निर्णय किया है, और

(घ) पिछले पाच वर्षों में कितनी कीमत के ताले निर्यात किये गये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) निर्यात के सरकारी आकड़े वस्तुवार रखे जाते हैं तथा कारखानेवार या क्षेत्रवार नही रखे जाते। फिर भी, चेकोस्लोवाकिया में अलीगढ़ के तालो के आयात में रुचि प्रकट की है तथा 1965-66 मे 16 लाख रुपये के तालो का आयात किया। पता चला है उसी देश के साथ लगभग 32 लाख रुपये मूल्य के एक और निर्यात आदेशो के सम्बन्ध में बातचीत चल रही हैं।

(ख) अलीगढ मे तालो की प्रमुख निर्यात फर्में निम्नलिखित है :—

1. मै० इंडियन इम्प्लीमेण्टस् मैन्यूफैक्चरिंग क०, अलीगढ़।
2. मै० एलन एण्ड अल्वन प्रा० लि०, अलीगढ़।
3. मै० एडन एण्ड कं० प्रा० लि०, अलीगढ़।
4. मै० इण्डियन ट्रेडिंग कार्पोरेशन, अलीगढ़।
5. मै० मोना एण्ड क०, अलीगढ़।
6. मै० वे एण्ड कं०, अलीगढ़।
7. मै० पी० पी० प्रोडक्टस, अलीगढ़।

(ग) निर्यात के लिये सरकारी सहायता कारखानेवार नहीं दी जाती परन्तु निर्यात वाली समस्त वस्तु पर दी जाती है : इस समय देय सहायता निम्नलिखित है :—

1. पीतल के ताले :

जहाज तक निःशुल्क मूल्य का 60 प्रतिशत आयात पुनर्भरण

जहाज तक निःशुल्क मूल्य की 10 प्रतिशत नकद सहायता

2. लोहे के ताले :

जहाज तक निःशुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत आयात पुनर्भरण

जहाज तक निःशुल्क मूल्य की 20 प्रतिशत नकद सहायता

(घ) गत पाच वर्ष मे तालों के निर्यात से उपार्जित विदेशी मुद्रा निम्नलिखित है :—

| वर्ष | मूल्य '000' रुपयों मे |
|---|---|
| 1962-63 | 642 |
| 1963-64 | 975 |
| 1964-65 | 1123 |
| 1965-66 | 2886 |
| 1966-67 (फरवरी 1967 तक) | 1098 |

Industrial Licensing

4295. Shri Yajna Datt Sharma:
Shri R. S. Vidyarthi:

Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state:

(a) whether a high power Study Team of Administrative Reforms Commission has recommended that the present system of Industrial Licensing should be given up;

(b) if so, whether Government have accepted the recommendations